

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2- आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 3-महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 14 मई, 2007

विषय:- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 दिनांक 10-5-2007 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15 जनवरी, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हुये उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001)(संशोधन) अध्यादेश, 2007 दिनांक 10-5-2007 प्रख्यापित किया गया है:-

क- मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) में व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी और नाबालिग संतान से है) भले ही वह धारा-129 के अधीन खातेदार या उत्तरांचल में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि कय कर सकता था। अध्यादेश के द्वारा अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि "कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिग संतान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु, भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तराखण्ड में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि कय कर सकता है"। अतः अब आवासीय प्रयोजन हेतु उक्त श्रेणी के व्यक्ति बिना अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर ही भूमि कय कर सकेंगे।

ख- मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) में व्यवस्था थी कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीद सकता है, जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले आउट प्लान अनुमोदित कर दिया गया है। अध्यादेश के द्वारा अब धारा 154 की उपधारा



(4)(2)(घ) का लोप (समाप्त) कर दिया गया है। इस संशोधन का परिणाम यह होगा कि अब कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदता है, जिसके पक्ष में ले आउट प्लान अनुमोदित है, तो 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि कय करने के लिये उसे शासन की अनुमति लेनी होगी, अन्यथा कय की गई भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

2- उक्त अध्यादेश के साथ ही उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2007 दिनांक 9-5-2007 भी प्रख्यापित की गई है, जिसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:-

क- मूल नियमावली के नियम 116-ट में यह व्यवस्था थी कि शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ-पत्र के आधार पर भूमि कय की जा सकेगी। संशोधित नियमावली में 90 दिन की समयसीमा को समाप्त करते हुये यह प्राविधान कर दिया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। अतः अब सब-रजिस्ट्रार 90 दिन के पश्चात शपथ-पत्र के आधार पर भूमि की रजिस्ट्री नहीं कर सकेंगे।

ख- मूल नियमावली के नियम 116-ठ में यह व्यवस्था थी कि कृषि एवं औद्योगिकी प्रयोजन हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र-ख में जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जाँच करायेंगे और प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुये भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुये (Speaking Order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को 90 दिन के अन्दर लिखित रूप से सूचित करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ पत्र के आधार पर भूमि कय की जा सकेगी। संशोधित नियमावली के द्वारा 90 दिन की समयसीमा को समाप्त करते हुये यह प्राविधान कर दिया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। अतः अब सब-रजिस्ट्रार 90 दिन के पश्चात शपथ पत्र के आधार पर भूमि कय की रजिस्ट्री नहीं कर सकेंगे।

3- अतः उक्त उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 दिनांक 10-5-2007 एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2007 दिनांक 9-5-2007 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतियाँ संलग्न

कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया इन संशोधनों के प्राविधानों को सभी अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें तथा इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नक-यथोपरि।

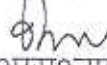
भवदीय

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी।
- 3- निजी सचिव, मा0राजस्व मंत्री जी।
- 4- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 10 मई, 2007 ई0

बैशाख 20, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1066/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007

देहरादून, 10 मई, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 पर दिनांक 10 मई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश सं0 01, सन् 2007 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)

(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2007)

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि भूमि की अनियंत्रित खरीद फरोख्त को नियंत्रित करने हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित :-

चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ एवं
विस्तार

1-(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2007 है।

(2) नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम
की धारा 154
की उपधारा (4)
(1)(क) का
प्रतिस्थापन

2-उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 154 की उपधारा (4)(1)(क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(4)(1)(क)-"इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं या परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिक सन्तान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता-पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तराखण्ड में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है।"

मूल अधिनियम
की धारा 154
की उपधारा (4)
(2) (घ) का
संशोधन एवं
लोप

3-(क) मूल अधिनियम के हिंदी पाठ की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) में उल्लिखित शब्द "नक्शा" को हटा दिया जायेगा।

(ख) मूल अधिनियम की धारा 154 की उपधारा (4)(2)(घ) का लोप कर दिया जायेगा।

सुदर्शन अग्रवाल,
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand (Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2007 (Uttarakhand Ordinance No. 01 of 2007).

As promulgated by the Governor of Uttarakhand assented to by 10th May, 2007.

No. 1066/XXVI(4)/2007
Dated Dehradun, May 10, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2001) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2007

(UTTARAKHAND ORDINANCE No. 01 OF 2007)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) in its application to the State of Uttarakhand to control the uncontrolled sale and purchase of agricultural land in the State of Uttarakhand

AN

ORDINANCE

Promulgated by the Governor in the Fifty Eighth year of the Republic of India:

WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (Amendment) Ordinance, 2007.

Short Title,
Extent and
Commencement

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once.

2. In place of existing sub-section (4) (1) (a) of section 154 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950) (Adaptation and Modification Order, 2001) (hereinafter referred to as principal Act) the following sub-section shall be substituted, namely :-

Amendment of
sub-section (4)
(1) (a) of section
154 of the
principal Act

(4)(1)(a)--Subject to other restrictions and save as otherwise provided in this Act, "any person for his own or on behalf of his family (which means husband, his wife, minor children, unmarried sons, unmarried daughters and dependent parents) even though he is not a tenure holder under section 129 or the owner of any immovable property in Uttarakhand, may purchase land not exceeding 250 sq. mts. for residential purpose in his lifetime without the permission".

3. (a) In sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the Hindi version of the principal Act, the word "Naksha" shall be omitted.

Amendment and
Omission of sub-
section (4) (2) (d)
of section 154 of
the principal Act

(b) Sub-section (4) (2) (d) of section 154 of the principal Act shall be omitted.

SUDARSHAN AGARWAL,
Governor, Uttarakhand.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

44/5
9/5/07

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त तथा समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 230, 294 तथा 344 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 (यथा उत्तरांचल में लागू) में कतिपय संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2007

1--(1) यह नियमावली "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (संशोधन) नियमावली, 2007" कही जायेगी।

संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2004, (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है), के निम्नलिखित स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 116-ट एवं नियम 116-ठ के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

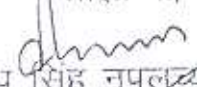
नियम 116-ट
एवं 116-ठ का
संशोधन

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम
116-ट शासन द्वारा भूमि कय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क) -शासन द्वारा प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर विचार करते हुए भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा। आवेदन-पत्र से 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ-पत्र के आधार पर भूमि कय की जा सकेगी। ऐसे शपथ पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र शासन को भेजी जायेगी। सम्बन्धित आवेदन कर्ता को यथा स्थिति	116-ट शासन द्वारा भूमि कय की पूर्व अनुमति, धारा 154(4)(3)(क) -शासन द्वारा प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा, तथा लिखित आदेश पारित किया जायेगा और सम्बन्धित आवेदनकर्ता को यथा स्थिति सूचित किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारित न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180

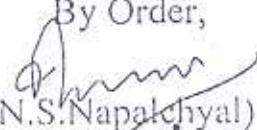
सूचित किया जायेगा। शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

116-ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि कय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख)-कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ पत्र कि कय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन पत्र प्रपत्र-ख के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्रति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जाँच करावेंगे और प्रत्येक मामले में गुणवोध के आधार पर विचार करते हुए भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (Speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को 90 दिन के अन्दर लिखित रूप से सूचित करेंगे। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 90 दिन के अन्दर ऐसी सूचना न मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा शपथ पत्र के आधार पर भूमि कय की जा सकेगी। ऐसे शपथ पत्र की प्रति रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार द्वारा यथाशीघ्र उस जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी, इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही कय की जा सकती है।

116-ठ जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु भूमि कय हेतु अनुमति देना, धारा 154(4)(3)(ख)-कृषि एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु इस आशय का शपथ-पत्र कि कय की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा आवेदन पत्र प्रपत्र-‘ख’ के साथ जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद आवेदक को तुरन्त दी जायेगी। जिला कलेक्टर प्राप्त आवेदन पत्र को एक पंजिका में तिथि सहित अंकित करेंगे, तथा ऐसी रीति से जैसा वे उचित समझें उस पर जाँच करावेंगे और प्रत्येक मामले में नियमानुसार विचार करते हुए भूमि कय की अनुमति देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे एवं कारण बताते हुए (Speaking order) आदेश पारित कर सम्बन्धित आवेदक को लिखित रूप से सूचित करेंगे। प्राप्त आवेदन पत्र का समुचित समयावधि में निस्तारण न किये जाने पर अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा पारित ऐसा आदेश, ऐसे आदेश की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगा। इस नियम के अधीन अधिकतम भूमि धारा 154(1) में दी गयी सीमा के अन्तर्गत ही कय की जा सकती है।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलवाला)
प्रमुख अधिकारी।

<p>an affidavit. A copy of such affidavit shall be forwarded immediately to the Govt. by Registrar /Sub Registrar. Orders passed under this rule shall be communicated to the applicant. Any sanction issued by the Govt. under this rule shall be valid for 180 days.</p>	<p>the Govt. under this rule shall be valid for 180 days.</p>
<p>116-K Prior sanction by the Collector of the District for the purchase of land for agricultural and horticultural purposes, section 154(4)(3)(b) – An affidavit to the effect that the land being purchased shall be used for agricultural or horticultural purpose an application in Form-B shall be presented to the Collector of the district. A receipt to this effect shall be given to the applicant. Collector of the district shall make entry such application in a register datewise and get it enquired in the manner he deems fit and pass a speaking order on merit allowing or rejecting the application for purchase of land within 90 days from the date of receipt of application. Order passed by Collector under this rule shall be valid for 180 days. From the date of submitting application if no sanction for purchase of land is received within 90 days by the applicant, the applicant can purchase land on furnishing an affidavit to this effect. A copy of such affidavit shall be sent by a Registrar/ Sub-Registrar to the Collector of the district Under this rule maximum land as provided u/s 154(1) can be purchased.</p>	<p>116-K Prior sanction by the Collector of the District for the purchase of land for agricultural and horticultural purposes, section 154(4)(3)(b) – An affidavit to the effect that the land being purchased shall be used for agricultural or horticultural purpose an application in Form-B shall be presented to the Collector of the district. A receipt to this effect shall be given to the applicant. Collector of the district shall make entry of such application in a register datewise and get it enquired in the manner he deems fit and pass a speaking order in accordance with the rules allowing or rejecting the application for purchase of land. For unreasonable delay in disposal of a received application within an appropriate timeperiod, responsibility would be fixed. Order passed by Collector under this rule shall be valid for 180 days. Under this rule maximum land as provided u/s 154(1) can be purchased.</p>

By Order,

 (N.S. Napatchyal)
 principal Secretary.

in pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 189/18(1)/2007, dated May, 2007.

Uttarakhand Shashan

Revenue Department

No. 189/18(1)/2007

Dated: Dehradun, 9 May, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by section 230, 294 and 344 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act, 1950 (U.P. Act no. 1 of 1904) read with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904, (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended time to time) the Governor is pleased to make the following rules with a view to make certain amendments in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Rules, 1952 (as applicable to the State of Uttarakhand) :-

The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1952) (Amendment) Rules, 2007

Short Title and Commencement 1. These rules may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1952) (Amendment) Rules, 2007.

2. They shall come into force at once.

Substitution of Rule 116-J and 116-K In the Uttaranchal (Now Uttarakhand) (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1952) (First Amendment) Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said Rules) for the existing rule 116-J and rule 116-K set out in column-1, the following rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

116-J Prior sanction by Govt. for purchase of land, section 154(4)(3)(a)- A decision on the basis of merit shall taken by the Govt. to give or not to give permission for purchase of land and a speaking order shall be issued in this respect. If after submitting desired application in Form -A to the Govt, if no orders are passed by the Govt. within 90 days the applicant shall be entitled to purchase the said land on furnishing	116-J Prior sanction by Govt. for purchase of land, section 154(4)(3)(a)- A decision in accordance with the rules shall be taken by the Govt. to give or not to give permission for purchase of land and a speaking order shall be issued in this respect. Orders passed under this rule shall be communicated to the applicant. For unreasonable delay in disposal of a received application within an appropriate timeperiod, responsibility would be fixed. Any sanction issued by
--	---